उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

8 अगस्त, 2018 • वर्ष 1, अंक 29

सात दिन – सात पृष्ठ

केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, सांसद अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा जी पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नई ट्रेन के शुभारम्भ के अवसर पर

- 939 करोड़ रूपये की योजनाओं से बदलेगी लखनऊ की तस्वीर
- उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 1.32 लाख लीटर की वृद्धि
- हर खेत को पानी उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प
- होमगार्ड्स स्वयंसेवको को मिलेगा रू. 500 प्रतिदिन मानदेय
- हर ब्लॉक में रखे जाएंगे लोक कल्याण मित्र
- अब आसानी से खाली हो सकेंगे अवैध कब्जे वाले सरकारी मकान

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

939 करोड़ रूपये की योजनाओं से बदलेगी लखनऊ की तस्वीर

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में कार्य शुरू हुआ। विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था को समाप्त करते हुए एक समान विद्युत वितरण व्यवस्था लागू की गई। वर्तमान सरकार ने मात्र 15 महीनों में ही 54 हजार 277 किमी. सड़कों का नवीनीकरण तथा 5,700 से अधिक बसावटों को मुख्य मार्गों, सड़कों और सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का काम किया गया है। निवेश की पहली शर्त सुरक्षा और दूसरी शर्त आम व्यापारी को मिलने वाली सुविधा है। यदि उद्यमियों को अच्छी सड़कें और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी, तो वे प्रदेश में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाएंगे। राज्य सरकार को पिछले 15 महीनों में इसमें काफी सफलता मिली है और अब प्रदेश में निवेश हो रहा है।

–योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित हो रहा है, क्योंकि वे इसके लिए पूर्ण समर्पित हैं। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य होगा। केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार लखनऊ के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

यह विचार केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित लखनऊ मण्डल की 939 करोड़ रुपए लागत की 308 विकास परियोजनाओं, लखनऊ महानगर के 4 एलीवेटेड मार्गों के निर्माण कार्य तथा वर्ष 2017 एवं 2018 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में आने वाले मेधावी विद्यार्थियों के ग्रामों/शहरी आवासों को जोड़ने हेतु 112 सम्पर्क मार्गों के शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा 'सबका साथ–सबका विकास ग्राम सड़क योजना' के अन्तर्गत 2918 ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए।

देश की सबसे सुन्दर राजधानी बनेगी लखनऊ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश की सबसे सुन्दर राजधानी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। लखनऊ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसे पूर्ण विकसित शहर बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

राजधानी लखनऊ के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विशेष योगदान है। उनकी प्रेरणा से ही शहीद पथ का निर्माण सम्भव हो सका था। इसके बनने से यातायात काफी सुगम हो गया है। लखनऊ के चारों ओर निर्मित की जा रही रिंग रोड से राजधानी में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

–राजनाथ सिंह

प्रदेश के विकास की धुरी बनेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम से जोड़ने की शुरुआत की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अपने 06 वर्ष के कार्यकाल में देश के बुनियादी ढांचागत विकास की नींव रखी थी। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर गम्भीरता से काम कर रही है, क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के विकास की धुरी बनेगा। ■

राज्य सरकार के प्रयासों का दिखने लगा असर

दुग्ध उत्पादन में 1.32 लाख लीटर की वृद्धि

दुग्ध उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय

प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास की व्यापक सम्भावनाएं हैं। डेयरी विकास के अनुकूल परिस्थितियां, आवश्यक संसाधन, मार्केट आदि सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। इन सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। नए डेयरी संयत्रों की स्थापना, नयी दुग्ध समितियों का गठन, किसानों को उन्नत प्रजाति के दुधारू पशुओं को उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में गोकुल पुरस्कार वर्ष 2017–18 के वितरण समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा इसके लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने के दुग्ध उत्पादन की बड़ी भूमिका हो सकती है। किसान खेती करते हुए भी दुग्ध उत्पादन कर सकता है। प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से अधिक है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या के दृष्टिगत दुग्ध समितियों की संख्या काफी कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम 60 हजार किया जाना चाहिए। दुग्ध विकास विभाग जितनी जल्दी यह लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, उतनी जल्दी ही किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी।

वर्ष 2017–18 में प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता जनपद लखीमपुर खीरी की दुग्ध समिति बेलवामोती के सदस्य श्री वरूण सिंह को 02 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार तथा जनपद मेरठ की दुग्ध समिति महिला नागौरी की सदस्य श्रीमती कुसुम को डेढ़ लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार मिला। वरूण सिंह ने वर्ष 2017–18 में 1,23,650.50 लीटर तथा श्रीमती कुसुम ने 96,023.89 लीटर दूध की आपूर्ति की है।

प्रदेश में हो रही है 10 डेयरियों की स्थापना

प्रदेश के 73 जनपदों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार के रूप में 51 हजार रुपए प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 17 महिलाएं भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित दुग्ध उत्पादकों की सराहना करते हुए कहा कि इन सबने 'जहां चाह वहां राह' के सूत्र के आधार पर सफलता प्राप्त की है। बिना प्रयास के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने प्रयास से सफल होकर आज सम्मानित हो रहे दुग्ध उत्पादकों का कार्य अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कार्यशैली सभी के सामने आनी चाहिए, जिससे अन्य लोग भी उसे अपनाकर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 10 डेयरियों की स्थापना तथा चार डेयरियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में पहले 60–70 डेयरियां थीं। इनके बन्द होने के कारणों का उपचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में डेयरी संयत्र स्थापित किए जाना आवश्यक हैं। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयास से दुग्ध उत्पादन में 1.32 लाख लीटर की वृद्धि हुई है, जो निरन्तर बढ़ रही है। ■

एकात्मवाद के प्रणेता को प्रदेश सरकार की श्रद्धांजलि

मुगलसराय जंक्शन अब कहलाएगा पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन

पं. दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। उन्होंने गांव को भारत के लिए विकेन्द्रीकृत राजनीति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में देखा। वे कमजोर वर्गों के पक्षधर थे और उन्होंने गरीबी में जीवनयापन करने वाले हर व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास किया। उन्होंने अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निरन्तर प्रयास किया। उनकी पावन स्मृति में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद चन्दौली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा करते हुए कहा कि रेल सेवाओं का सुधार एवं विस्तार किया जायेगा। पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन यार्ड का ''स्मार्ट यार्ड'' में उन्नयन, रूट रिले इन्टरलॉकिंग प्रणाली तथा स्टेशन का भी विकास किया जायेगा। जंक्शन पर वैगन जांच हेतु 32 करोड़ रुपए से स्मार्ट यार्ड का विकास तथा सिग्नल प्रणाली के संचालन हेतु रूट रिले इन्टरलॉकिंग प्रणाली का 190 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जायेगा।

पं. दीन दयाल जी का सपना था कि समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का शत- प्रतिशत लाभ मिले। हर गरीब के पास अपना घर हो, शौचालय (इज्जत घर) हो। इस सपने को सच साबित करना है।

–योगी आदित्यनाथ

पहली महिला क्रू मेंबर्स द्वारा परिचालित मालगाड़ी की शुरूआत

इस अवसर पर पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेन की शुरूआत भी की गई। पहली बार पूर्णतः महिला क्रू मेम्बर द्वारा परिचालित मालगाड़ी का परिचालन भी प्रारंभ हुआ। इस मालगाड़ी के चालक, सहायक चालक, गार्ड, स्टेशन मास्टर रख–रखाव के लिए महिला सुपरवाइजर, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल, स्टेशन स्टाफ सभी महिलाएं ही होंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश नये विकास के आयाम गढ़ रहा है।

– अमित शाह

74 करोड़ की लागत से बनेगा पं. दीनदयाल उपध्याय स्मृति स्थल

पं. दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति को अक्षुण्ण रखने और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने हेतु 74 करोड़ की लागत से पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्थल, पड़ाव चौराहे का शिलान्यास भी किया गया। परियोजना के प्रथम चरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 39.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

कांवड़ यात्रा | **गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक किया कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण**

योगी ने हेलीकाप्टर से बरसाए फूल...खूब लगे जयकारे

कांवड़ यात्रा में डीजे पर लगी रोक हटाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का दिल तो पहले ही जीत चुके थे, गत दिवस उन्होंने हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा कर कांवड़ यात्रा के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करने के साथ-साथ शिवभक्तों और आमजन का मान भी बढ़ा दिया। ऊपर से बरसते फूलों में सेवा की सुगंध थी तो नीचे लगते हर जयकारे में योगी की कर्तव्यनिष्ठा और संकल्प पूरा करने की गूंज भी। लाखों भक्तों ने जब बम-बम के बीच 'फिर से योगी' का उद्घोष किया तो एक सपना साकार सा होता दिखा।

मुजफ्फरनगर में हेलीकाप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करते मुख्यमंत्री योगी

नजारा देखने को उमड़ा हुजूम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिवस गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ पटरी मार्ग का हेलीकाप्टर से निरीक्षण किया। इस शानदार नजारे को देखने के लिये जगह-जगह घंटों पहले से ही हुजूम लग गया। लखनऊ से नोएडा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पहले अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की।

दीदार के लिए उठी रहीं निगाहें

बैठक के बाद अपराह्न लगभग चार बजे मुख्यमंत्री नोएडा से हेलीकाप्टर द्वारा रवाना हुए। उनके साथ मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार व अन्य अधिकारी भी रहे। उन्होंने गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक इस शानदार नजारे को हेलीकाप्टर से ही निहारा और जगह-जगह कांवडियों पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की।

अभिवादन किया तो गदगद हुई जनता

मेरठ से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र तक हेलीकाप्टर ने दो चक्कर लगाये। उड़ान के दौरान कई बार हेलीकाप्टर काफी नीचे तक आया तो योगी जिंदाबाद के नारे लगे तो चारों दिशाएं गूंज उठीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाईवे पर कांवड़ियों की तरफ हाथ हिलाकर उन्हें खुद अभिवादन किया तो कांवड़ियों ने भी हाथ हिलाते हुए अपने मन के भाव उन तक पहुंचा दिए। ■

साभार: दैनिक जागरण

वर्तमान सरकार ने महिलाओं को **भयमुक्त वातावरण** देने का कार्य किया है। महिलाओं तथा बालिकाओं को राहत प्रदान करने तथा उनकी मदद के लिए **महिला हेल्पलाइन '181'** संचालित की है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस हेल्पलाइन के तहत रेस्क्यू वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, **विमेन पावर लाइन '1090'** को और प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि **'एण्टी रोमियो स्क्वॉयड'** के गठन के बाद से महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है। राज्य में घटते हुए लिंगानुपात पर रोक लगाने के लिए **मुखबिर योजना** शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।

–मुख्यमंत्री

सरकार ने महिलाओं को भयमुक्त वातावरण देने का कार्य किया है : सीएम

प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता और कल्याण के लिए हर सम्भव कदम उठाने का काम कर रही है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण एवं नारी शक्ति के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समाज को भी आगे आकर अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने यह विचार लखनऊ में **'नारी के प्रति हिंसा रोकने में मीडिया, स्कूल व समाज की भूमिका'** विषय पर आयोजित 8वें अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के अवसर पर व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में नारी हिंसा एक ज्वलंत समस्या है। नारी हिंसा को रोकने में मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मीडिया ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को समय–समय पर मार्गदर्शन देने का काम किया है। किसी भी समस्या के समाधान में समाज के हर वर्ग को अपना योगदान देना होगा, तभी हम खुशहाल समाज की स्थापना कर सकते हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु सोनभद्र में स्थापित होगी सोलर लैम्प बनाने की कम्पनी

ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को सशक्त बनाकर स्वरोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में सोलर लैम्प बनाने की पहली कम्पनी सोनभद्र में स्थापित की जायेगी। इससे आस–पास के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की रोजगार के साथ ही आमदनी बढ़ेगी। सरकार द्वारा 70 लाख सोलर लैम्प वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 3.70 लाख लैम्प बच्चों को वितरित किये जा चुके हैं।

बुन्देलखण्ड में होगी डेरी की स्थापना

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है, इसके साथ ही प्रदेश की सरकार महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए विभिन्न

योजनाओं में उनकी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए डेरी की स्थापना की जायेगी और इसका संचालन महिलाएं करेंगी।

कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार

केन्द्र व राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। सरोजनीनगर विकास खण्ड में 600 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसके साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी सुलभ कराये जा रहे है।

सामाजिक सद्भाव में बढ़ोत्तरी

महिलाओं के उत्थान में स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका है। स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता से महिलाओं में जहां एक ओर आत्मविश्वास बढ़ा है वही दूसरी ओर साहूकारी प्रथा से भी छुटकारा मिला है। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ जुड़ने से सामाजिक सदभाव में बढ़ोत्तरी हुई है और भेद–भाव जैसी कुरीतियों पर भी अंकुश लगा है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी विकास खण्ड अधिकारियों को महिला समूहों को जागरूक करने के निर्देश दिये गये हैं। सरकार द्वारा 29 जनपदों के 115 विकास खण्डों में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। ■

वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि

जी.एस.डी.पी. में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित

उत्तर प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय) के वर्ष 2015–16 (संशोधित अनन्तिम अनुमान) वर्ष 2016–17 (संशोधित त्वरित अनुमान) व वर्ष 2017–18 (संशोधित अग्रिम अनुमान) के जी.एस.डी.पी. में स्थिर भावों पर क्रमशः 8.8, 7.3 एवं 6.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। यह आंकड़े अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2015–16 (संशोधित अनन्तिम अनुमान) वर्ष 2016–17 (संशोधित त्वरित अनुमान) व वर्ष 2017–18 (संशोधित अग्रिम अनुमान) के सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान स्थिर (2011–12) एवं प्रचलित भावों पर तैयार कर जारी किये गये है।

वर्ष 2015–16 में स्थिर (2011–12) तथा प्रचलित भावों पर (बाजार मूल्यों पर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) क्रमशः 907700.41 करोड़ रूपये तथा 1137209.60 करोड़ रूपये, वर्ष 2016–17 में क्रमशः 974119.96 करोड़ रूपये तथा 1250213.39 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 1036148.54 करोड़ रूपये तथा 1375607.02 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया है, जो कि स्थिर भावों पर क्रमशः 8.8, 7.3 व 6.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 47062, 51014 व 55339 रूपये अनुमानित की गयी, जो कि पिछले वर्ष से क्रमशः 11.3 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

होमगार्ड्स स्वयंसेवको को अब मिलेगा रू. 500 प्रतिदिन मानदेय

अब उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रतिदिन मानदेय के रूप में 375 रुपये के स्थान पर 500 रुपये मिलेंगे। होमगार्ड्स जवानों के कल्याण कोष की राशि भी 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गयी है। इसके अतिरिक्त, होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय की अवशेष देनदारी 71 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में होमगार्ड्स के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि होमगार्ड्स विभाग का प्रदेश पुलिस के सहयोगी बल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल रहा है।

उन्होंने कहा कि अवस्थापना सुविधाओं की वृद्धि से कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई सुविधाओं से होमगार्ड्स स्वयंसेवक अपने दायित्वों के निर्वहन को और कुशलतापूर्वक ढंग से सम्पादित कर सकेंगे।

होमगार्ड्स के ड्यूटी अवसरों में बढ़ोत्तरी

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक होमगार्ड्स विभाग कई समस्याओं का सामना करता रहा है। स्वयंसेवकों की निरन्तर ड्यूटी की भी समस्या रही है, जिसके मद्देनजर वर्तमान सरकार ने ड्यूटी अवसरों में वृद्धि की। आज होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को अधिक ड्यूटियां प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभाग की मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके चरणबद्ध निराकरण की कार्ययोजना लागू की गयी। वर्तमान सरकार ने इस संगठन की अनेक समस्याओं का समाधान किया है।

महिला सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर करें कार्य

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होमगार्ड्स संगठन के विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। इस संगठन को समय की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न अवसरों के लिए अपने को तैयार करना होगा। शान्ति व्यवस्था, यातायात प्रबन्धन और आपदा के समय पुलिस के सहयोगी संगठन के रूप में होमगार्ड्स प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। आज सुरक्षा का कार्य एक चुनौती है। होमगार्ड्स, सुरक्षा और खासतौर से महिला सुरक्षा के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड्स कार्यालय के 14 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित 4 भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए 27 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को 3–3 लाख रुपये के चेक वितरित किये। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गयी है। उन्होंने अच्छी वर्दी, अच्छे टर्न, अनुशासन एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 10 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को विभागीय पदक से सम्मानित भी किया।

बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता हेतु तत्पर है उत्तर प्रदेश सरकार

केन्द्र व प्रदेश की सरकार किसी भी आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आपदा की स्थिति में सरकार द्वारा हर सम्भव और तत्काल मदद करने का प्रबन्ध किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कि बाढ़ के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि कतई न हो तथा पीड़ितों को हर सम्भव मदद अतिशीघ्र मुहैया कराई जाए। जलभराव वाले गांवों के लोगों को तत्काल राहत कैम्पों में विस्थापित करने का काम आरम्भ कर दिया गया है तथा कैम्पों में विस्थापितों को हर प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

राहत कैम्पों में जीवनरक्षक दवाओं के साथ अन्य आवश्यक दवाओं, भोजन, पेयजल, जानवरों के चारे इत्यादि की उपलब्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जा रही है। जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संगठनों के लोगों से आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की जा रही है।

माह अगस्त और सितम्बर में बरसात की अधिक सम्भावना के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन कर अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इन क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जाएगी, जिससे जनधन की हानि न हो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, क्लोरीन की टैबलेट बांटने, एंटीलार्वा छिड़काव करने तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं जानवरों को चारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण

आपदा के सम्बन्ध में बेहतर उपायों एवं पूर्व तैयारियों से जन-धन की हानि न्यूनतम की जा सकती है: मुख्यमंत्री

बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की समुचित उपलब्धता

हर खेत को पानी उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प

कच्ची नाली, पक्की नाली , चकरोड का निर्माण तथा जल निकासी का होगा बंहतर प्रबन्ध

बुन्देलखण्ड में अधिक से अधिक तालाबों का होगा निर्माण किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

भूमि संरक्षण एवं सिंचन के कार्य प्राथमिकता पर होगे पूरे

हर खेत को पानी उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। सरकार ने सिंचाई कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे किसानों को खेती के लिए सिंचाई की दिक्कत न हो। काडम योजना के तहत कच्ची नाली, पक्की नाली, चकरोड का निर्माण तथा जल निकासी का बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। बुन्देलखण्ड में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए अधिकाधिक तालाबों का निर्माण किया जायेगा।

किसानों को सिंचन आदि की सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए तालाबों एवं चेक डैमों के निर्माण कार्य को ससमय पूर्ण किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरुप होंगे।

विशेषज्ञ करेंगे विकास कार्यों की जांच

भूमि संरक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भूमि संरक्षण एवं सिंचन के कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए और सही रिपोर्ट दें। विकास कार्यो की जांच विशेषज्ञों द्वारा कराई जाएगी और कार्य मानक अनुरुप न पाए जाने या कार्य में लापरवाही बरते जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

किसानों के लिए संचालित योजनाओं का होगा प्रचार

जिन मण्डलों/इकाइयों में शारदा सहायक के निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम कार्य हुआ है, उन मण्डलों के क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कृषकगण सिंचाई की आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर सकें। मण्डल तथा जिले में जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी बनाकर समुचित प्रचार कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

7 अगस्त 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

हर ब्लॉक में रखे जाएंगे लोक कल्याण मित्र, 25 हजार होगा वेतन

यूपी सरकार ने सरकारी योजनाओं को गांव–गांव तक पहुंचाने और पात्र लोगों की मदद करने के लिए हर ब्लॉक पर एक लोक कल्याण मित्र तैनात करने का फैसला किया है। 822 ब्लॉकों पर इसकी तैनाती की जाएगी। इन्हें 25 हजार मासिक वेतन व 5000 रूपये तक का यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा।

एक साल के इन्टरशिप कार्यक्रम के तहत लोक कल्याण मित्र तैनात होंगे। चयन में शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। हर तीन महीने पर उनके काम की समीक्षा होगी। एक साल बाद सीएम के अनुमोदन से उनकी तैनाती एक साल और बढ़ सकेगी। एक मित्र के जिम्मे उस ब्लॉक के सभी गांव होंगे। प्रदेश स्तर पर केवल दो लोक कल्याण मित्र मुख्यालय पर तैनात होंगे। चयन के बाद उनकी ट्रेनिंग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, गिरी इंस्टीट्यूट और प्रबन्धन संस्थाओं में होगी।

चयन हेतु आवश्यक योग्यता :

- **कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग या किसी भी विषय में स्नातक व दो साल का कार्य अनुभव**
- **21 से 40 साल तक की आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र**
- **कम्प्यूटर में एमएस ऑफिस की जानकारी रखने वालों को प्राथमिकता।**

केजीएमयू में फिर होगी प्रति कुलपति की नियुक्ति

कानपुर में यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में मौजूद निष्प्रोज्य स्पिनिंग भवन और लैब होंगे ध्वस्त

यमुना एक्सप्रेस–वे और प्रस्तावित ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे की क्रासिंग बनेगी ग्राम जगनपुर, अफजलपुर के पास (इंटरचेंज)

राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए नौ करोड़ रूपये की एकमुश्त व्यवस्था

अब आसानी से खाली हो सकेंगे अवैध कब्जे वाले सरकारी मकान

कैबिनेट ने राज्य सम्पत्ति विभाग की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली–2018 को मंजूरी दे दी। इस नियमावली के लागू हो जाने के बाद अवैध कब्जे खाली करवाने के लिए विहित प्राधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे पुलिस बल की मदद से 15 दिन के भीतर कार्रवाई की जा सकेगी।

'उज्ज्वला योजना' के माध्यम से देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मिला नि:शुल्क गैस कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के माध्यम से देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई दी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 87 लाख कनेक्शन वितरित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में 67 लाख व तीसरे स्थान पर बिहार में 61 लाख कनेक्शन वितरित किये गये। प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से कमजोर 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 'उज्ज्वला योजना' का शुभारम्भ प्रदेश के बलिया जनपद से मई, 2016 में किया था। सरकार द्वारा 3 वर्ष में इन लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे निर्धारित अवधि के 8 माह पूर्व पूरा कर लिया गया।

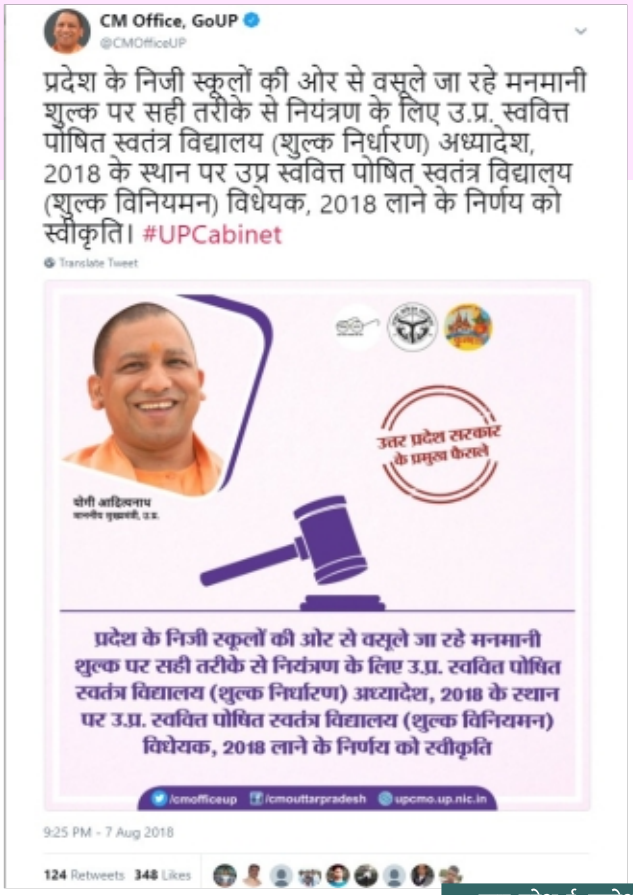

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी